

प्रेषक,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 30 सितम्बर, 2010

विषय:- ग्राम हर्षिल, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी में उद्योग विभाग की खाली पड़ी खसरा संख्या-4681 म० कुल 0.030 है० भूमि, सहायक आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार के कार्यालय एवं आवासीय परिसर हेतु पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5796/11-2/2009-10, दिनांक-22.5.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति के दृष्टिगत, ग्राम हर्षिल, पट्टी टकनौर, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी में उद्योग विभाग की खाली पड़ी खसरा संख्या-4681 म० कुल 0.030 है० भूमि, सहायक आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार के कार्यालय एवं आवासीय परिसर हेतु, वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य एवं उक्त भूमि के मालगुजारी के सौ गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा० राकेश कुमार)
सचिव।

पृ०प०सं०- 1017 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. उप निदेशक, सहायक आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार, 17/1 इंजीनियर्स एन्क्लेव, जी०एम०एस०रोड, देहरादून।
5. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय। ✓
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।